

प्रेषक,

टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक ०7 जून, 2005

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में पुलों के निर्माण एवं सुदृढीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1 के पत्र सं० 527 ए./XXVII (1)/2005 दिनांक 26.4.2005 के क्रम में आपके पत्र संख्या-100/01 बजट(सेतु कार्य-स.से.)-11/2005-06, दिनांक 06.04.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में पुलों के निर्माण एवं सुदृढीकरण के चालू कार्यों हेतु रुपये 1500.00 लाख (रु० पंद्रह करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का सी०सी०एल० के अनुसार त्रैमासिक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओं पर प्रथमतः 75 प्रतिशत कार्यवार खण्डवार आबंटन का संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जायेगा। जिन खण्डों में 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नहीं हैं उन खण्डों में 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किये जायें तथा वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर त्रैमासिक रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराने समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का आहरण कैश क्रेडिट सीमान्तर्गत ही नियमानुसार यथाआवश्यकता किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि नार्बार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. 8 व 9 योजना में स्वीकृत समस्त पुलों के अवशेष कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जायें।

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग करके जनपदवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

- 9- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राजमार्ग-आयोजनागत-101-पुल-03 पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण -00-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।
- 10- यह आदेश वित्त विभाग के अ.स. सं- 183 /वित्त अनुभाग-3/05, दिनांक, 09 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-665 (1)/111(2)/05, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून ।
- 2- सचिव श्री राज्यपाल, सचिवालय, देहरादून ।
- 3- आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मंडल, पौड़ी/नैनीताल ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, सो० नि० वि०, पौड़ी/ अल्मोड़ा ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 7- निजी सचिव, मुख्य मंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ हेतु ।
- 8- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
- 9- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून ।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन
- 11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।